भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2756
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- पश्चिम बंगाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
2756. श्री अबू ताहेर खानः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के लिए जूट तथा धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या है;
(ख) पश्चिम बंगाल में समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है/क्या कदम उठाए गए हैं, और
(ग) किसानों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के, अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए धान व पटसन सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है।

विपणन सीज़न 2026-27 के लिए धान और पटसन के मौजूदा एमएसपी का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए प्रति क्विंटल)

धान	(सामान्य)	2441
	(ग्रेड ए)	2461
पटसन		5925

जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने लगता है तब कुल उत्पादन में से केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, दिशानिर्देशों के अनुसार, तब की जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है। खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है कि बढाई गई एमएसपी से पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2014-2026 (जून 2026 तक) के दौरान अखिल भारतीय एवं पश्चिम बंगाल की खरीद और किसानों को दी गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है।

	अखिल भारतीय		**पश्चिम बंगाल**	
	खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ में)	खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ में)
धान	8548	1639511.30	336.15	62764.43
पटसन	3.18	1341.66	2.27	947.68

पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में धान की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए, केएम्एस 2025-26 के लिए 620 सेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सेंटर (सीपीसी) और 179 मोबाइल सेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सेंटर (एम् सीपीसी) बनाए रखे गए हैं। मोबाइल सीपीसी को रणनीतिक रूप से दूर-दराज़ और दुर्गम गांवों में तैनात किया गया है। किसानों को राज्य सरकार के सेंट्रलाइज़्ड और मोबाइल प्रोक्योरमेंट सेंटरों पर अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, केएम्एस 2025-26 के लिए एम्एसपी (₹2,369/क्विंटल) के साथ ₹20/क्विंटल की प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से तीन कामकाजी दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पहलों में तेज़ी से और पारदर्शी खरीद के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑनलाइन किसान पंजीकरण, आधार प्रमाणीकरण, बैंक सत्यापन और ई-पैडी पोर्टल के माध्यम से स्वयं-शेड्यूलिंग शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (जेसीआई) राज्य में सात क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 69 डिपार्टमेंटल परचेज़ सेंटर्स (डीपीसीएस), साथ ही एम्पैनल्ड एजेंसियों और मोबाइल खरीद ऑपरेशन्स के ज़रिए एम्एसपी ऑपरेशन्स चलाता है। एम्एसपी ऑपरेशन्स को मज़बूत करने के लिए, जेसीआई ने पात-मित्रों, स्लॉट बुकिंग सिस्टम, जेसीआई सहयोग प्लेटफ़ॉर्म और जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जेसीआईएस) के ज़रिए सैटेलाइट-आधारित फ़सल निगरानी जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। इसके अलावा, यह सर्टिफ़ाइड बीज वितरण, किसान जागरूकता कार्यक्रम और वैज्ञानिक रेटिंग इंटरवेंशन जैसे काम भी करता है।

*****